इंडसइंड का मुनाफा 58प्रतिशत और सेंट्रल बैंक का 64 फीसदी बढ़ा, ग्रॉस एनपीए रहा 2.06 प्रतिशत

नई दिल्ली ।
इंडसइंड बैंक को दिसंबर तिमाही में 1,964 करोड़ का मुनाफा हुआ है जो दिसंबर, 2021 के 1,242 करोड़ की तुलना में 58प्रतिशत ज्यादा है। सकल बुरा फंसा कर्ज (ग्रॉस एनपीए) 2.06 फीसदी रहा। इसका जमा 3.25 लाख करोड़ और कर्ज 2.84 लाख करोड़ रुपये रहा। सेंट्रल बैंक ने बुधवार को बताया कि दिसंबर तिमाही में फायदा 64प्रतिशत बढ़कर 458 करोड़ रहा जो 2021 में 279 करोड़ रुपये था। बैंक की कुल आय बढ़कर 7,635 करोड़ रुपये रही। शुद्ध एनपीए 4.39प्रतिशत से घटकर 2.09प्रतिशत रहा।

एसबीआई ने जुटाए 9,718 करोड़ रुपये - भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बुधवार को कहा, उसने 9,718 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से जुटाए हैं। इस पर वह 7.70 फीसदी ब्याज देगा। बैंक ने कहा इस रकम का उपयोग लंबी अवधि के लिए दिए जाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर और सस्ते घरों के कर्ज पर किया जाएगा। इस बॉन्ड की अवधि 15 साल की होगी।

वित्त मंत्रालय ने मांगा अंतिम अनुदान के लिए खर्च प्रस्ताव - संसद के बजट सत्र से पहले वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुदान की दूसरी एवं अंतिम अनुपूरक मांगों को लेकर खर्च प्रस्ताव देने को कहा है। मंत्रालय ने ज्ञापन में कहा कि 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच को संसद के आगामी सत्र में रखे जाने का प्रस्ताव है। सभी मंत्रालयों विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वीकृत संशोधित अनुमान सीमा के तहत खर्च नियंत्रित करें।

लग्जरी मकानों की कीमतों में 12 फीसदी तक उछाल - देश के प्रमुख शहरों में 2022 में लग्जरी या महंगी संपत्तियों की कीमतें 8-12 फीसदी बढ़ी हैं। इसके साथ ही कीमतें 2015 के पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गईं। इंडिया सोथबीज इंटरनेशनल रियल्टी ने रिपोर्ट में कहा, 2023-24 में 61 फीसदी धनाढ्य व अति धनाढ्य लोग महंगे घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। सर्वे में शामिल 65 फीसदी लोग 4-10 करोड़ और 33 फीसदी 10 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की संपत्ति खरीदना चाहते हैं।

न्यूज ब्रीफ

अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा ज्यादा ब्याजः केनरा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की

नई दिल्ली। केनरा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। अब केनरा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने पर 3.25 से लेकर 7.15 तक का ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरों के अनुसार अगर अब आप केनरा बैंक में 1 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं तो आपको सालाना 6.75प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 2 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.80, 3 साल और 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.50प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वहीं बैंक 400 दिन की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.15प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। आप एक साल में फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो भी ब्याज कमाते हैं, वो आपकी एनुअल इनकम में जुड़ता है। कुल आय के आधार पर, आपका टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है। चूंकि फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है, इसलिए इसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के तहत चार्ज किया जाता है। जब आपका बैंक आपकी ब्याज आय को आपके अकाउंट में जमा करता है, तो उसी समय काट लिया जाता है। यदि आपकी कुल आय एक वर्ष में 2.5 लाख रुपए से कम है, तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर नहीं काटता है। हालांकि, इसके लिए आपको फॉर्म 15 जमा करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप बचाना चाहते हैं तो फॉर्म 15जरूर जमा करें।

निदेशक बोलीं- हम भारत में 200 परियोजनाओं पर काम कर रहे, इनमें 37 अरब डॉलर का निवेश संभव

नई दिल्ली । यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी भारत में 200 ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही जिसमें करीब 37 अरब डॉलर के निवेश की संभावना बनेगी। संस्थान की निदेशक इनोह टी इबोंग ने बुधवार दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि ये 200 प्रोजेक्ट्स स्वच्छ ऊर्जा के ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल ढांचा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं। इबोंग ने कहा, हमारा अनुमान है कि ये परियोजनाएं करीब 37 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करेंगी। हम ऐसी परियोजनाएं तैयार करते हैं जिन्हें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और बहुपक्षीय बैंकों की ओर से वित्त पोषित किया जा सकता है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन परियोजनाओं को लागू किया जाए और निवेशकों को परियोजनाओं में विश्वास हो। भारत के हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर यूएसटीडीए की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यूएसटीडीए नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में भारत के साथ सहयोग में रुचि रखता है। उन्होंने कहा मैंने देश की योजनाओं के बारे में बहुत कुछ सुना है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कें लिए नई तकनीक विकसित करने में सहयोग करने में हम बहुत रुचि रखते हैं।

फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में जल्द होगी छंटनीः स्विगी अपने 6,000 के टोटल वर्कफोर्स में से 8-10प्रतिशत एम्प्लॉइज को निकालेगी

नई दिल्ली । फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी में जल्द ही छंटनी होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्विगी फंडिंग स्लोडाउन के बीच छंटनी के एक और राउंड पर विचार कर रही है। कॉस्ट को रेशनेलाइज बनाने के लिए फूड एंड ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपने 6,000 के टोटल वर्कफोर्स में से 8-10प्रतिशत एम्प्लॉइज की छंटनी करने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार छंटनी में प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग और ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है। स्विगी ने पहले कहा था कि वह पहले ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल होने का लक्ष्य बना रही है, जो हाल के महीनों में टेक स्टॉक्स के खराब परफॉर्मेंस के कारण इस साल के लेटर हाल्फ में डिले हो गया है। कंपनी ने अक्टूबर 2022 में अपने परफॉर्मेंस रिव्यू को पूरा किया था। जिसके बाद सभी एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के तहत रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, स्विगी के एम्प्लॉइज पर काम का भारी दबाव है, क्योंकि मैनेजमेंट नंबर्स हासिल करने के लिए टीमों में फेरबदल लॉन्च करने से पहले पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स को प्रभावित कर रहा है।

10प्रतिशत डिस्काउंट में खरीदें अडाणी के शेयर : 27 जनवरी को खुल रहा अडाणी एंटरप्राइजेज का एफपीओ

मुंबई।
अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर 27 जनवरी को खुल रहा है। इसका प्राइस बैंड 3,112-3,276 रुपए प्रति शेयर है। अगर प्राइस बैंड के निचले हिस्से को देखे तो शेयर करीब 10प्रतिशत डिस्काउंट पर मिल रहा है। एफपीओ में रिटेल निवेशकों को 64 रुपए प्रति शेयर की छूट भी दी जाएगी। एफपीओ में मिनिमम बिड लॉट 4 शेयर और उसके बाद 4 शेयरों के मल्टिपल में है।

कंपनी 100प्रतिशत बुक-बिल्ट ऑफर के तहत पार्ट्ली पेड बेसिस पर नए शेयर जारी करेगी। एफपीओ के तहत, एम्प्लॉई कोटा 5प्रतिशत, रिटेल 35प्रतिशत और नॉन-इंस्टीट्यूशनल 15प्रतिशत निर्धारित किया गया है। एंकर इन्वेस्टर के लिए एफपीओ दो दिन पहले यानी 25 जनवरी को खुलेगा। एफपीओ के तहत मिले शेयरों को डीमैट अकाउंट में 7 फरवरी तक क्रेडिट किया जाएगा। 8 फरवरी से ये शेयर ट्रेड के लिए उपलब्ध होंगे।

एक्सपेंशन और कर्ज कम करने में मदद - सिक्योरिटीज, जेफरीज कैपिटल मार्केट्स को एफपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। एफपीओ से जुटाई रकम गौतम अडाणी को एक्सपेंशन और कर्ज कम करने में मदद करेगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एफपीओ के कारण गौतम अडाणी के नेतृत्व वाले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब 3.5प्रतिशत घटेगी।

डिस्काउंट पर शेयर खरीदने का मौका - स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट में इक्विटी मार्केट हेड गिरीश सोडानी ने कहा, एफपीओ रिटेल निवेशकों के लिए डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर स्टॉक खरीदने का एक अच्छा मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक ने अतीत में अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रुप ने नए बिजनेसेज में प्रवेश किया है और अपने बिजनेस का तेजी से विस्तार किया है। सितंबर तिमाही में, कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिस साल-दर-साल दोगुना से ज्यादा बढ़कर 460.94 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना लगभग तीन गुना बढ़कर 38,175.23 करोड़ रुपए हो गया।

प्रमोटर्स की 72.63प्रतिशत हिस्सेदारी - सितंबर 2022 तक, प्रमोटरों के पास अडाणी एंटरप्राइजेज का 72.63प्रतिशत हिस्सा था, जबकि शेष 27.37प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास पब्लिक शेयरहोल्डर्स के बीच 4.03प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि नोमुरा सिंगापुर, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, एलारा इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड और एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड के पास 1प्रतिशत और 2प्रतिशत के बीच हिस्सेदारी थी।

एफपीओ क्या है - एफपीओ यानी फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में पहले से लिस्टेड कंपनी मौजूदा शेयरधारकों या नए निवेशकों को नए शेयर जारी करती है। यह अलग है जहां कंपनी फंड इकट्ठा करने के लिए पहली बार अपने शेयर जारी करती है। एफपीओ के जरिए कंपनी अपने इक्विटी बेस का विस्तार करती है।

एफपीओ में क्या होता है - एफपीओ में जारी शेयर की कीमत मार्केट प्राइस से कम होती है। कम कीमत पर शेयर जारी करने के पीछे प्राथमिक मकसद इसके इश्यू के लिए ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करना होता है। हालांकि, सब्सक्रिप्शन में शेयर की कम कीमत होने के कारण अकसर बाजार मूल्य भी नीचे आ जाता है और वो एफपीओ प्राइस के करीब पहुंच जाता है।

शेयर में 3.50प्रतिशत की गिरावट - अडाणई एंटरप्राइजेज के एफपीओ का प्राइस बैंड घोषित होने के बाद इसके शेयर में गिरावट देखी जा रही है। अडाणी का शेयर करीब 130 रुपए या 3.50प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,463.60 रुपए पर कारोबार कर रहा है।

एफपीओ के लिए अप्लाय कैसे करें - एफपीओ के लिए भी अप्लाय करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। इसे अप्लाय करने की प्रोसेस भी है। अडाणी एंटरप्राइजेज का सब्सक्रिप्शन ओपन होने के बाद 4 शेयर की मिनिमम बिड लगाई जा सकती है। उससे ज्यादा शेयर चाहिए तो 4 के मल्टिपल में बिड कर सकते हैं। जितने शेयरों के लिए अप्लाय करेंगे उतना अमाउंट आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा।

बेहद कठिन काम संभाल रही हैं, सीतारमण पर बोले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, बजट पर दी ये सलाह

नई दिल्ली ।
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बड़ी टिप्पणी की है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान राजन ने कहा कि सीतारमण एक बेहद कठिन कार्य संभाल रहीं हैं। रघुराम राजन जो भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार की ज्यादातर पॉलिसीज के आलोचक रहे हैं उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कहा है कि वे एक कठिन कार्य कर रहीं हैं, ऐसे में मैं अच्छे या बुरे के रूप में उनके कार्य का मूल्यांकन करने वाला कोई नहीं होता।

दावोस में जब एक पत्रकार ने राजन से पूछा कि वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को क्या रैंक देंगे तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें रैंक नहीं दे सकता, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे एक कठिन कार्य कर रहीं हैं, ऐसे में जो व्यक्ति काम कर रहा है उन्हें मैं कोई रैंकिंग नहीं दे सकता है।

रघुराम राजन ने कहा कि असली चिंता लोअर मिडिल क्लास की है। राजन के अनुसार इस वर्ग को लेकर अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चिंता है। यहां रोजगार की कमी है। बड़े व्यवसाय बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने अपने कर्ज का भुगतान महामारी के दौरान भी किया। बैंकों ने भी अपना बैड लोन राइट ऑफ कर दिया है। ऐसे में बैंक और बड़े कारोबार आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पर दिक्कत लोअर मिडिल क्लास के साथ है।

कोरोना के दौरान उनमें से कुछ लोगों की नौकरियां तक चली गईं हैं। छोटे और मध्यम उद्योग अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे फिर से बेहतर करने की कोशिशों में जुटे हैं, वे वापस लौट रहे हैं। इस वर्ष 7प्रतिशत का विकास दर रहना शानदार है।

उन्होने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमने अच्छी वृद्धि की पर बाद के महीनों में विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। हम 5प्रतिशत के दर पर आ गए जो कि चिंता की बात है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं को देखते हुए लगता है कि यह पांच प्रतिशत से भी नीचे जाएगा, यही चिंता की बात है और इसलिए हम वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हो सकते।

ईवी स्पेयर पार्ट्स पर एक समान जीएसटी की उम्मीदः बजट में फेम सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा करेगी सरकार, कस्टमर को मिलेगा सीधा फायदा

नई दिल्ली।
सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) को उम्मीद है कि सरकार ईवी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना जारी रखेगी। इसके साथ ही उम्मीद है कि सरकार इस बजट में घरेलू स्तर पर आर एंड डी को बढ़ावा देने, सप्लाई संबंधी दिक्कतों को दूर करने और मजबूत ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए नई योजनाएं और उपाय भी लाएगी। एसएमईवी डीजी सोहिंदर सिंह गिल ने बताया कि उम्मीद है कि सरकार बजट में फेम सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा करेगी और इसका लाभ सीधे ग्राहक को ट्रांसफर करने के प्रावधान लागू होंगे। एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 5प्रतिशत है। वहीं स्पष्टता नहीं होने की वजह से स्पेयर पार्ट्स पर 28प्रतिशत तक जीएसटी चुकाना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि सरकार सभी ईवी स्पेयर पार्ट पर यूनिफॉर्म 5प्रतिशत जीएसटी की दर लागू करेगी। ईवी उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले लिथियम आयन सेल पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 0प्रतिशत करने से ईवी की लागत घटाने में मदद मिलेगी।

फेम 2 की वैधता मार्च 2024 में समाप्त हो रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार ईवी इंडस्ट्री को सहारा देने में मददगार इस स्कीम को आगे बढ़ाने की घोषणा भी इस

बजट में करेगी। यह भी उम्मीद है कि फेम 2 स्कीम में ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे। इससे सब्सिडी सीधे कस्टमर के खाते में ट्रांसफर हो। भारत की ईंधन खपत में ट्रकों की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। अगर सकरार फेम का दायरा कमर्शियल वाहनों यानी ट्रकों और ट्रैक्टर्स तक भी बढ़ाती है तो इससे ईवी ट्रक और ट्रैक्टर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और ईंधन की खपत के साथ उत्सर्जन में भी कमी आएगी। देश में बीते 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, ऐसे में लिथियम आयन बैटरियों की रिसाइकलिंग के लिए नीति बनाया जाना बहुत आवश्यक है।

माइक्रोसॉफ्ट में सबसे बड़ी छंटनी, टेक कंपनियों ने छह दिन में 30611 कर्मचारियों को निकाला

नई दिल्ली।
वैश्विक मंदी के डर से दुनियाभर की प्रौद्योगिकी कंपनियां बड़े स्तर पर छंटनी कर रही हैं। दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी पांच फीसदी यानी 11,000 तक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट में इसे अब तक की सबसे बड़ी छंटनी माना जा रहा है। कंपनी जुलाई में भी 1,000 कर्मियों को निकाल चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि आज हम ऐसे बदलाव कर रहे हैं, जो हमसे जुड़े व्यक्ति के लिएचुनौतीपूर्ण है। निकाले जाने वाले कर्मचारियों को सूचना दे दी गई है। इसमें से कुछ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इस कदम से कंपनी को करीब 1.2 अरब डॉलर की बचत होगी। इस बीच, विभिन्न रिपोर्ट में कहा गया है कि नौकरियों के लिहाज से नए साल की शुरुआत खराब रही है। अमेजन समेत अन्य कंपनियां जनवरी के पहले छह दिनों में 30,611 लोगों को निकाल

चुकी हैं। शेयरचैट ने भी 20 फीसदी छंटनी की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि प्रभावित कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान के साथछह महीनों तक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जाएंगी।साथ ही, उन्हें दो महीने पहले नौकरी से निकालने का नोटिस दिया जाएगा। मॉर्निंगस्टार के विश्लेषक डैन रोमनॉफ के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट में छंटनी का एक और दौर बताता है कि हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र जल्द स्थिर नहीं होने वाला है। नौकरियों के लिहाज से आगे हालात और खराब होंगे।

माइक्रोसॉफ्ट में 30 जून, 2022 तक करीब 2.21 लाख कर्मचारी थे। इनमें 1.22 लाख कर्मचारी अमेरिका में कार्यरत हैं, जबकि 99,000 भारत समेत अन्य देशों में हैं। देश की चार सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक में भर्तियों में 97 फीसदी की गिरावट आईहै। रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 की दिसंबर तिमाही में चारों कंपनियों ने शुद्ध रूप से 1,940 कर्मचारी जोड़े।यह पिछली 11 तिमाहियों में सबसे कम भर्ती है।2021-22 की समान तिमाही में इन चारों कंपनियों ने 61,137 लोगों को नौकरियां दी थीं।चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से तुलना करें तो भर्तियां 94 फीसदी घटी हैं। दिसंबर, 2022 तक टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या 2,197 घट गई।इस दौरान कंपनी का एट्रिशन रेट भी घटकर 21.3प्रतिशत रह गया।

देश में आसमान क्यों छू रहे गेहूं के भाव पिछले साल की तुलना में 16प्रतिशत चढ़े दाम

नई दिल्ली ।
एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में गेहूं की कीमतें 3000 रुपये प्रति क्विंटल के पार पहुंच गईं हैं। इसका कारण पूर्वी भारत में अनाज की कमी है। अनाज कारोबार से जुड़े लोगों और कारोबारियों ने इसकी पुष्टि की है। बाजार के जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार ने गेहूं को खुले बाजार में ओएमएसएस (ओपन मार्केट सेल स्कीम) के तहत बेचने की पहल अब तक नहीं की है। इस कारण गेहूं की कीमतें रोज नई ऊंचाई पर पहुंच रही हैं। भारतीय रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन (आरएफएमएफआई) के अध्यक्ष प्रमोद कुमार का मानना है कि खुले बाजार में गेहूं नहीं है। पूर्वी भारत में भी गेहूं उपलब्ध नहीं है। जब से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गेहूं का आवंटन रोका है, खुले बाजार में इसकी मांग बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की कीमतें रोज नई ऊंचाई पर पहुंच रही हैं। देश का उत्तरी सूबा गेहूं की किल्लत का सामना कर रहा है। नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर दक्षिण भारत के एक व्यापारी ने ये बातें कही। दिल्ली स्थित एक कारोबारी के अनुसार गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य यूपी को इसे गुजरात से खरीदना पड़ रहा है। बाजार के जुड़े लोगों के अनुसार उत्तर

प्रदेश में गेहूं की कीमतें 3050 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं हैं। वहीं राजस्थान में यह अनाज 2800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा है। मीलरों को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग से उठाना पड़ रहा है। कृषि मंत्रालय की इकाई एगमार्केट के आंकड़ों के अनुसार आठ जनवरी को गेहूं के भाव 2788 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। पिछले साल की तुलना में ये करीब 20 फीसदी अधिक है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खुदरा बाजार में गेहूं के भाव करीब 31.17 रुपये प्रति किलो हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.76 फीसदी ज्यादा है। वहीं गेहूं का आटा 37.03 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। गेहूं की कीमतें 2022 के रबी सीजन में तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में लगातार बढ़ते रहे हैं। वर्ष 2023 के खरीफ सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार अनाजों खासकर गेहूं और चावल के मामले में आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतें हैं। यह स्थिति उत्पादन के आंकड़ों पर भी संदेह पैदा करता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल अपने लक्ष्य 60 लाख टन अनाज खरीदारी के लक्ष्य की तुलना में अब तक सप्लाई की कमी के कारण महज 20 लाख टन अनाज की खरीदारी ही कर पाया है। ट्रेड एनालिस्ट्स मानते हैं कि महंगाई के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि कोर महंगाई दर में कमी नहीं आई है क्योंकि अनाज की कीमतों में उछाल जारी है। जानकारों के मुताबिक गेहूं के भाव अगले पखवाड़े तक 3300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकते हैं। यह स्थिति फरवरी महीने के अंत या मार्च की शुरुआत तक बनी रह सकती है। तब तक गुजरात में गेहूं की नई फसल बाजार में आ जाएगी।

आरएफएमएफआई के प्रमोद कुमार के अनुसार उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों में गेहूं के फसल की आवक मार्च महीने के अंत तक शुरू होगी। इस स्थिति में केंद्र सरकार को अपने कोटे स्टॉक से ओएमएसएस स्कीम के तहत अनाज की बिकवाली करनी पड़ सकती है।

एयरबैग में खराबी के चलते मारुति सुजुकी वापस मंगाएगी 17,362 कारें, ब्रेजा और बलेनो भी शामिल

नई दिल्ली । एयरबैग में खराबी के चलते मारुति सुजुकी 17,362 गाड़ियों को वापस मंगाएगी। इनमें ऑल्टो के10, ब्रेजा और बलेनो शामिल हैं। एयरबैग नियंत्रक फिर से पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। कंपनी ने बुधवार को बताया कि एस-प्रेसो, ईको और ग्रैंड विटारा के भी एयरबैग में खराबी मिली है। इन कारों को 8 दिसंबर, 2022 से 12 जनवरी, 2023 के बीच बनाया गया है। जरूरत पड़ी तो एयरबैग को मुफ्त में बदला जाएगा। संभावित डिफेक्ट के कारण वाहन दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग और सीट बेल्ट प्रेटेंसर काम नहीं कर सकते हैं। जब तक खराब पुर्जे को नहीं बदला जाता तब तक वाहन न चलाएं। टाटा नेक्सन ईवी के बेस ट्रिम की कीमत 14.99 लाख रुपए से 50,000 रुपए घटकर 14.49 लाख रुपए हो गई है। नेक्सन ईवी मैक्स में एक नया वैरिएंट एक्सएम भी जुड़ा है। इसकी कीमत 16.49 लाख से शुरू है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *
फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017